सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹02

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

कानपुर, बुधवार, 23 जुलाई, 2025
वर्षः 02, अंकः 197, पृष्ठः 8+4

'धर्म' को बीजेपी का हथियार बताया

» Pg 12

इनसाइड छह महीने से फिसड्डी बना कानपुर... » Pg 03

गाजियाबाद में अवैध 'दूतावास' का पर्दाफाश

» मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने सोमवार को गाजियाबाद में एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए एक फर्जी 'विदेशी दूतावास' का भंडाफोड़ किया है। कविनगर निवासी हर्षवर्धन जैन पुत्र जे.डी. जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो खुद को West Arctica, Saborga, Poulvia, Lodonia जैसे कथित माइक्रोनेशन देशों का कॉन्सुल/राजदूत बताकर लोगों को ठग रहा था।

हर्षवर्धन ने गाजियाबाद के केबी-35 कविनगर में किराए के मकान को 'दूतावास' बनाकर वहां से फर्जीवाड़े और अंतरराष्ट्रीय दलाली का जाल फैला रखा था। वह डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगी लग्जरी गाड़ियों से चलता था और लोगों पर प्रभाव जमाने के लिए खुद को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य हाई-

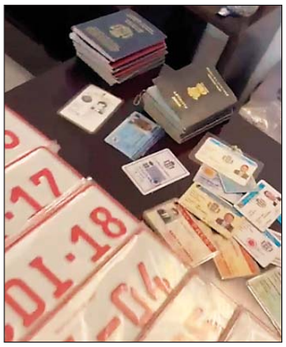

प्रोफाइल हस्तियों के साथ फोटोशॉप से एडिट तस्वीरों के माध्यम से प्रस्तुत करता था। एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि हर्षवर्धन कंपनियों और प्राइवेट व्यक्तियों को विदेश में नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूलता था और शेल कंपनियों के जरिए हवाला रैकेट भी संचालित करता था। उसके तार पूर्व में कुख्यात चंद्रास्वामी और इंटरनेशनल आर्म्स डीलर अदनान खगोशी से भी जुड़े रहे हैं। 2011 में भी उसके पास से अवैध सैटेलाइट फोन बरामद हो चुका है, जिसकी एफआईआर थाना कविनगर में दर्ज है।

आरोपी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज : थाना कविनगर में आरोपी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच के लिए संबंधित केंद्रीय एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार, इस फर्जीवाड़े का नेटवर्क देश-विदेश तक फैला हुआ है और इसमें कुछ उच्च प्रोफाइल संपर्क भी सामने आ सकते हैं। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। यह मामला फर्जी राजनयिक नेटवर्क, हवाला और अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी की मिली-जुली साजिश का गंभीर उदाहरण है,

बड़ी बरामदगी

- 4 डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियां
- 12 फर्जी डिप्लोमैटिक पासपोर्ट
- विदेश मंत्रालय की नकली मोहरों वाले कूट रचित दस्तावेज
- दो फर्जी पैन कार्ड
- 34 फर्जी मुहरें (कंपनियों और विदेशी एजेंसियों की)
- दो नकली प्रेस कार्ड
- 44,70,000 रुपए नगद
- विभिन्न देशों की विदेशी मुद्रा
- 18 फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट
- दस्तावेजों का ढेर, जिनमें कई कंपनियों से संबंधित कागजात शामिल

कार्यक्रम जल्द घोषित होगा

उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग की ओर से जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा किए जाने की संभावना है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, अगले कुछ दिनों में तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी।

कार्रवाई एलआईयू जांच में खुलासा, थानों में "सेटिंग" का था खेल

मथुरा पुलिस : 27 पुलिसकर्मी एक साथ लाइन हाजिर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

» कई हमराही पुलिसकर्मी थानों में दलाली का नेटवर्क चला रहे

» एसएसपी ने स्वयं के स्तर पर भी जांच कराकर की कार्रवाई

मथुरा। जनपद मथुरा में पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएसपी श्लोक कुमार ने 27 पुलिसकर्मियों को एक साथ लाइन हाजिर कर दिया है। ये सभी पुलिसकर्मी थाना प्रभारी निरीक्षकों के हमराह थे और आरोप है कि ये लोग थानों में आने वाले वादी-प्रतिवादी से "सेटिंग" कराने में दलाली करते थे।

इस कार्रवाई से पहले लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (एलआईयू) की विस्तृत जांच कराई गई थी। जांच में सामने आया कि कई हमराही पुलिसकर्मी थानों में दलाली का नेटवर्क चला रहे थे, जहां वादी और प्रतिवादी को थाना प्रभारी से सेटिंग कराने के नाम पर मोलभाव किया जाता था। एसएसपी ने स्वयं के स्तर पर भी जांच कराई और सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद कार्रवाई की।

विभाग में मचा हड़कंप, 21 थानों के पुलिसकर्मी शामिल : लाइन हाजिर किए गए 27 पुलिसकर्मी जनपद के 21 विभिन्न थानों में तैनात थे। इनमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल हैं, जो लंबे समय से थाना प्रभारियों के साथ हमराह के रूप में नियुक्त थे। कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।

एसएसपी श्लोक कुमार ने स्पष्ट किया कि "किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस की छवि और जनविश्वास को खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।" लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों के स्थान पर अब पुलिस लाइन में तैनात ईमानदार और अनुशासित कर्मियों की तैनाती थानों में की जाएगी।

यह कार्रवाई मथुरा पुलिस प्रशासन के लिए एक कड़ा संदेश है कि पुलिसिंग में पारदर्शिता और ईमानदारी सर्वोपरि है।

घाटमपुर से मधुसूदन यादव का तूफानी जनसंपर्क, गांव-गांव मिला अपार समर्थन

प्रमुख संवाददाता दैनिक स्वराज इंडिया

कानपुर(घाटमपुर)। जैसे-जैसे पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है, प्रत्याशियों ने भी मैदान में उतरकर अपना प्रचार अभियान तेज़ कर दिया है।

घाटमपुर की चौबेपुर जिला पंचायत सीट से लोकप्रिय समाजसेवी मधुसूदन यादव ने शुक्रवार को क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में तूफानी दौरा कर लोगों से आशीर्वाद लिया और समर्थन की अपील की। जनसंपर्क अभियान के दौरान नौजवानों, बुजुर्गों और महिलाओं ने जगह-जगह उनका तिलक व मालाओं से जोरदार स्वागत किया। यादव को लेकर क्षेत्र में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं, जनता ने भी विकास के वादे के साथ उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का भरोसा दिया।

» फूल-मालाओं से हुआ भव्य स्वागत, जनता ने जताया भरोसा

» बोले- चुनाव बाद नहीं, हर दिन रहूंगा जनता के साथ

मधुसूदन यादव ने इस अवसर पर कहा, मैं चुनाव जीतने के बाद गायब होने वाला नहीं हूं, बल्कि 365 दिन, 24 घंटे हर सुख-दुख में आपके साथ खड़ा मिलूंगा।उनके इस जनसंपर्क अभियान के बाद स्थानीय जनता में जहां उत्साह है, वहीं विरोधी खेमे में खलबली भी देखी जा रही है।इस मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे, जिनमें मोहित यादव, रोहित यादव, तौसीफ अहमद, ध्रुव, उमेश, सद्दाम, हाशिम, कमल, रवि शंकर, अंकित सिंह, विक्रम यादव, आदर्श गुप्ता, आदित्य साहू, सिझान यादव, रितेश, राहुल, रुद्रा, बाबू सिंह आदि शामिल रहे।

खुशी की लहर

निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित शिक्षकों को राहत

अब नहीं कटेगा वेतन, सीएल से होगा समायोजन

दुकानें कराईं बंद,मरम्मत शुरू होने के बाद खिसकी गई थी मिट्टी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। अब यदि कोई शिक्षक स्कूल निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाया जाता है और उसके पास शेष आकस्मिक अवकाश (सीएल) है, तो उसका वेतन नहीं काटा जाएगा। उस दिन की अनुपस्थिति को सीएल से समायोजित किया जाएगा। यह व्यवस्था शिक्षकों के लंबे समय से हो रहे एकतरफा वेतन कटौती के संकट से उन्हें बचाएगी।

अब तक की प्रक्रिया में, अगर कोई शिक्षक निरीक्षण के समय कुछ देर से भी स्कूल पहुंचता था या किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाता था, तो बीएसए, बीईओ या अन्य निरीक्षणकर्ता अधिकारी उसे प्रेरणा पोर्टल पर अनुपस्थित चिह्नित कर देते थे। परिणामस्वरूप, शिक्षक का वेतन तुरंत काट लिया जाता था, और बाद में सिर्फ स्पष्टीकरण मांगने की औपचारिकता की जाती थी। तब तक शिक्षक को आर्थिक और मानसिक क्षति हो चुकी होती थी।

अब महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा जारी किए गए नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई शिक्षक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिलता है, तो पहले यह देखा जाएगा कि उसके पास सीएल शेष है या नहीं। यदि सीएल उपलब्ध है, तो अनुपस्थिति उसी में समायोजित कर दी जाएगी, जिससे वेतन कटौती नहीं होगी।

शिक्षक संगठनों ने किया फैसले का स्वागत

इस निर्णय का शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह आदेश शिक्षकों के साथ हो रहे अनुचित व्यवहार और शोषण पर लगाम लगाएगा। साथ ही, इससे शिक्षकों को मानसिक राहत मिलेगी और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी मिलेगा। फ्यह निर्णय शिक्षकों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम है। अब बिना वेतन कटौती के शिक्षक अपनी स्थिति समझा सकेंगे।

यह नया आदेश शिक्षकों के लिए न्याय और संवेदनशीलता की ओर बढ़ता कदम है। इससे जहां एक ओर शिक्षकों को अनावश्यक दंड से राहत मिलेगी, वहीं प्रशासन के सामने जवाबदेही की एक नई मिसाल भी स्थापित होगी।

आईजीआरएस रैंकिंग में छह महीने से फिसड्डी बना कानपुर

राहुल पांडेय, स्वराज इंडिया

कानपुर। जनशिकायतों के समाधान के लिए बने आईजीआरएस पोर्टल पर कानपुर जिला लगातार नाकाम साबित हो रहा है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के छह महीने के कार्यकाल में भी इस सिस्टम में कोई ठोस सुधार नहीं हो पाया है। मार्च को छोड़ दिया जाए तो हर महीने कानपुर की रैंक 60वें स्थान के पार रही है। डीएम के तमाम सख्त आदेश, फटकार और प्रयोग भी हवा-हवाई साबित होता दिख रहा है।

- डीएम की चेतावनियां और प्रयोग हुए बेअसर, अफसरों पर नहीं पड़ा कोई असर
- आईजीआरएस निस्तारण के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी हो रही है

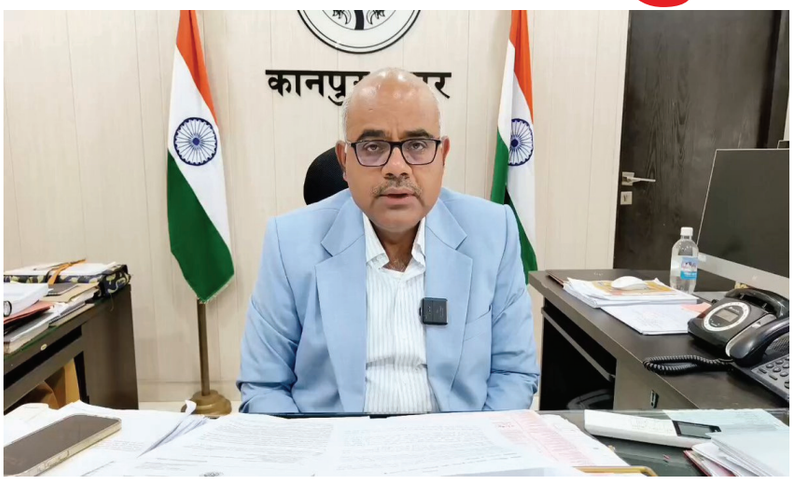

आईजीआरएस रैंकिंग में गिरावट को लेकर डीएम ने जून में 44 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें जनपद, तहसील और नोडल अधिकारियों को लापरवाही के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया। मगर नतीजा? न तो फीडबैक सुधरा, न ही रैंकिंग। अफसरों की निष्क्रियता और कर्मचारियों की उदासीनता खुलकर सामने आ रही है।

डीएम की सख्ती पर भी नहीं डोले अफसर

खास खबर

फरवरी में डीएम ने सख्त लहजे में कहा था कि काम करना है तो जिले में रहो, वरना तबादले के लिए तैयार रहो, मगर यह चेतावनी भी अफसरों पर असर नहीं डाल सकी। शिकायतों की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की फौज तैनात की गई है, लेकिन वह भी 'ढाक के तीन पात' साबित हो रही है।

मार्च को छोड़ दिया जाए, तो बाकी महीने कानपुर की रैंक 60 से ऊपर रही है। इसका सीधा मतलब है कि डीएम के प्रयोग और अफसरों की रिपोर्टिंग केवल कागजों में है, ज़मीनी असर नदारद।

नया आदेश, नई उम्मीद... लेकिन कितनी कारगर?

अब डीएम ने नया आदेश जारी किया है कि हर शिकायत का निस्तारण निर्धारित तिथि से तीन दिन पहले अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि जब पिछले आदेशों को अफसर ठेंगा दिखा चुके हैं, तो इस बार क्या अलग होगा?

कानपुर की आईजीआरएस रैंकिंग में लगातार गिरावट जिला प्रशासन की नाकामी को उजागर कर रही है। चाहे सख्ती हो, चेतावनी हो या प्रयोग—सब कुछ नाकाम साबित हो रहा है। अगर यही हाल रहा, तो आईजीआरएस जनता की उम्मीदों का नहीं, सिर्फ अफसरों की असंवेदनशीलता का आईना बनकर रह जाएगा। अब ज़रूरत है सिर्फ चेतावनी नहीं, ठोस कार्रवाई की। वरना कानपुर की रैंकिंग और जनता दोनों प्रशासन से मुंह मोड़ लेंगे।

हर महीने गिरती रैंक, हर बार वही बहाना

महीना	रैंक	प्रतिशत
फरवरी	61वीं	73.57 प्रति.
मार्च	41वीं	75.71 प्रति.
अप्रैल	61वीं	73.57 प्रति.
मई	68वीं	73.57 प्रति.
जून	65वीं	74.29 प्रति.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए बाबा आनंदेश्वर के दर्शन

- बोले कई जन्मों का पुण्य मिला
- डीएवी कॉलेज के छात्रकाल की यादें साझा करते हुए भावुक हुए पूर्व राष्ट्रपति
- मानव कल्याण और विश्व शांति की कामना के साथ की पूजा-अर्चना

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। सावन माह की शिवरात्रि पर बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर स्थित श्री बाबा आनंदेश्वर परमठ धाम पहुंचकर दर्शन और पूजन किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि आज उन्हें कई जन्मों का पुण्य प्राप्त हुआ है। सुबह करीब 10 बजे भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पूर्व राष्ट्रपति का काफिला आनंदेश्वर मंदिर पहुंचा। मंदिर में प्रवेश के बाद उन्होंने महंत और ब्राह्मणों के साथ विधिवत जलाभिषेक और आरती की।

इस मौके पर भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी और मेयर प्रमिला पांडे भी उनके साथ मौजूद रहीं।

दर्शन के बाद रामनाथ कोविंद भावुक हो गए। उन्होंने अपने छात्र जीवन की यादें साझा करते हुए बताया कि जब वे

डीएवी कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे, तब प्रतिदिन सुबह बाबा आनंदेश्वर के दर्शन करने आया करते थे।

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, गंगा मां भी इस मंदिर को नमन करती थीं, और आज मैं भी उसी श्रद्धा से आया हूं।

मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, केवल मानव कल्याण, देश की उन्नति और विश्व शांति की प्रार्थना की है।

उन्होंने कहा कि जैसा इस मंदिर का नाम है आनंदेश्वर, वैसे ही यहां आने से आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है।

दर्शन के बाद वे पुलिस सुरक्षा में वहां से रवाना हो गए।

तहसील लेखपाल संघ चुनाव में जितेंद्र अध्यक्ष और सुनील मंत्री बने

मंत्री पद पर सुनील ने 9 वोटों से मारी बाजी, अध्यक्ष पद पर जीतेंद्र ने 11 मतों से हासिल की जीत

पूर्व तहसील अध्यक्ष ललित व बार एसो. महामंत्री महेन्द्र नवनिर्वाचित सदस्य को सम्मानित करते हुए।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष व मंत्री को प्रमाण पत्र देते तहसीलदार अनुभव चंद्र।

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। तहसील लेखपाल संघ चुनाव में इस बार मुकाबला जितना रोचक था, परिणाम उतने ही निर्णायक निकले। मंगलवार को हुए चुनाव में सुनील चौधरी ने मंत्री पद पर 9 मतों से जीत हासिल की, जबकि अध्यक्ष पद पर जीतेंद्र यादव ने 11 वोटों से बाजी मारी। इस चुनावी परिणाम ने संगठन में नए समीकरणों की नींव रख दी है। सुनील चौधरी को कुल 42 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी प्रमोद को 33 वोट प्राप्त हुए।

उधर, अध्यक्ष पद के मुकाबले में जीतेंद्र यादव को 43 वोट हासिल हुए, वहीं शिवशंकर 32 मतों के साथ पीछे रह गए। सुबह से ही तहसील परिसर में मतदान को लेकर गहमागहमी थी। कहीं हल्के अंदाज़ में हंसी-ठिठोली चल रही थी तो कहीं गंभीर चर्चा और जोड़तोड़ की रणनीति बनती दिखी। लेकिन परिणाम ने साफ कर दिया कि इस बार मतदाताओं ने अनुभव और सादगी के मेल को चुना। जीत के बाद सुनील चौधरी ने कहा कि यह सिर्फ मेरी जीत नहीं, बल्कि उन तमाम साथियों की जीत है जो बिना शोर के संग रहे। संगठन की सेवा के लिए समर्पित रहूंगा। वहीं अध्यक्ष पद जीतने के बाद जीतेंद्र यादव बोले कि यह जिम्मेदारी है, शोहरत नहीं। हम सब मिलकर संगठन को और मजबूत करेंगे। सभी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष व मंत्री को फूल-माला पहनाकर बधाई दी। लेखपाल संघ चुनाव में वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र पाल सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सुधांशु सिंह, उप मंत्री स्वाति राजपूत, कोषाध्यक्ष ऋषभ दुबे एवं ऑडिटर पंकज सोनकर निर्विरोध निर्वाचित हुए। इन सभी पदों पर किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। उधर नव निर्वाचित सदस्यों को तहसीलदार बिल्हौर अनुभव चंद्र ने बधाई दी साथ ही पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र सौंपे

किसने साथ दिया कौन बेवफ़ा निकला! : तहसील लेखपाल संघ चुनाव के नतीजे आते ही गुटों का गणित अब खुले में नहीं, बल्कि दबी आवाज़ों में गूंजने लगा है। जीत की चकाचौंध के पीछे भीतरघात का अंधेरा टटोलने का खेल तेज़ हो गया है। जीते हुए प्रत्याशी अब समथज़न में खड़े चेहरों को दोबारा देख रहे हैं। कहीं जो सबसे ऊंची आवाज़ में हमारे लिए बोलता थाज वही तो चुपचाप पराए खेमे में वोट नहीं डाल गया? उधर, हारे हुए उम्मीदवारों की टीम अब बैठकों में नहीं, बल्कि मन के अंदर हिसाब-किताब चला रही है। जीत वाले आँकड़ा लगा रहे कि इतने कम वोट से जीते और हार वाले आँकड़ा जोड़ रहे आखिर हारे कैसे। अब दोनों वो चेहरे तलाश कर रहे हैं कौन साथ रहा किसने बेवफाई की।

निजी पलों में खलल डालने वाला

तीसरा आरोपी शिवम बहेलिया भी गिरफ्तार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। युवक-युवती के निजी पलों में खलल डालने और शर्मनाक हरकत को अंजाम देने

वाले तीसरे आरोपी शिवम बहेलिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया है। इससे पहले इस प्रकरण में आरोपी कुलदीप और अरुण को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

पुलिस ने कराई शादी

कन्नौज से मनावा तक इश्क ने काटा समाज का रास्ता

छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथी मरते दम तक

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। इश्क़ जब बस की सीट से शुरू हो और थाने के मंदिर तक पहुंचे, तो कहानी आम नहीं रह जाती।दो दिलों ने समाज की बंदिशों, घर वालों की नाराजगी और हर रुकावट को दरकिनार कर ये ऐलान कर दिया कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथी मरते दम तक। जानकारी के मुताबिक कन्नौज जनपद के ठठिया कस्बा निवासी अरुण कुमार और ककवन के मनावा गांव की सोनम की दोस्ती कॉलेज के दिनों में बस सफर के दौरान शुरू हुई थी। दोनों एक ही कॉलेज में

जोड़े को आशीर्वाद देते पूर्व जिला पंचायत सदस्य अखिलेश अवस्थी।

» पढ़ाई के दौरान रोजाना बस में साथ में आना जाना होता था

» थाने में स्थित शिव मंदिर में दोनों ने पूरे रीति से शादी की

स्नातक की पढ़ाई करते थे और रोजाना बस में साथ आना-जाना होता था। यही रोज की मुलाकातें धीरे-धीरे प्यार में बदल गईं। लेकिन जैसे ही बात शादी तक पहुंची, परिवार वालों ने विरोध शुरू कर दिया। मंगलवार को अरुण ने जब एक बार फिर घरवालों के सामने शादी की बात रखी, तो मामला इतना बढ़ा कि वो सोनम को लेकर ककवन थाना पहुंच गया। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता और वहां मौजूद पूर्व जिला पंचायत सदस्य अखिलेश अवस्थी ने पूरी बात समझी। दोनों बालिग थे। फिर क्या था, थाने में बने शिव मंदिर में पूरे रीति-रिवाज से दोनों की शादी करवा दी गई। फूलमालाएं, सिंदूर, चुनरी और मंगलसूत्र ये सब पुलिसवालों ने खुद जुटाया। थाने में जब दोनों ने एक-दूजे को वरमाला पहनाई, तो वहां मौजूद लोगों ने बधाई दी।

सम्पादकीय

वैवाहिक विवादों में अब होगी सबूत

संक्रमणकाल से गुजर रहे भारतीय समाज में पति-पत्नी के दरकते रिश्ते समाजविज्ञानियों के लिए चिंता का विषय हैं। आये दिन विभिन्न अदालतों में ऐसे मामलों से जुड़े विवाद मीडिया की सुर्खियां बनते रहते हैं। निस्संदेह, भारतीय समाज में पहले ऐसे मामले कम ही नजर आते थे और विवाह को सात जन्मों का बंधन कहा जाता रहा है। यहां तक कि हिंदू विमर्श में तलाक शब्द का कोई सटीक पर्यायवाची भी नहीं मिलता। लेकिन इधर रिश्तों में लगातार बढ़ता अविश्वास, अलगाव व विवाद वर्तमान समय की हकीकत है। बल्कि पिछले दिनों एक न्यायाधीश को यहां तक कहना पड़ा कि वैवाहिक विवादों के बोझ से न्यायिक प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा है। इसी क्रम में पिछले दिनों पति-पत्नी के विवाद में गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई फोन कॉल को साक्ष्य मानने की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों से जुड़े एक अहम फैसले में कहा है कि पति या पत्नी द्वारा गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत अब एक सबूत के तौर पर स्वीकार होगी। शीर्ष अदालत का कहना था कि इस तरह की रिकॉर्डिंग फैमिली कोर्ट में एक अहम सबूत के तौर पर स्वीकार की जा सकती है। दरअसल, इस बाबत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को ही रद्द कर दिया। दरअसल, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का इस बाबत मानना था कि किसी पक्ष की जानकारी के बिना उसकी बातचीत को रिकॉर्ड करना उसकी निजता का उल्लंघन होगा। उच्च न्यायालय का तर्क था कि इस रिकॉर्डिंग को फैमिली कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय का कहना था कि आमतौर पर पति-पत्नी सामान्य तौर पर या आवेश में खुलकर बात करते हैं। उन्हें इस बात का भान नहीं होता कि कहीं उनकी बात रिकॉर्ड हो रही है या उनकी बातचीत भविष्य में अदालत में साक्ष्य की तौर पर पेश की जा सकती है।अपने तर्क के समर्थन में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने कुछ न्यायिक फैसलों का भी जिक्र किया था। खासकर आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पति-पत्नी की सहमति के बिना बातचीत को रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन है। साथ ही गैर-कानूनी भी है। इस तरह के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उन दलीलों को अस्वीकार्य किया कि जिसमें कहा गया था कि इस तरह के साक्ष्य की अनुमति देने से घरेलू सौहार्द व वैवाहिक रिश्तों पर आंच आएगी। यह भी कि इससे समाज में पति-पत्नी की जासूसी की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साक्ष्य अधिनियम का भी अतिक्रमण होगा। शीर्ष अदालत की पीठ का इस बाबत कहना था कि अदालत में पहुंचे रिश्ते इस बात का पर्याय हैं कि दोनों के रिश्ते सहज व सामान्य नहीं हैं।

दूरगामी रणनीति से बनेंगे पड़ोसियों से अच्छे संबंध

क्षमा शर्मा

हमें दुश्मनों, आगे उनके दोस्तों और उनकी क्षमताओं की भी अच्छी समझ बनाए रखनी होगी। हम स्वीकारें कि इस मामले में, फिलहाल हम लगभग अकेले पड़े हैं, और दोस्तों और हमारे सशस्त्र बलों के लिए पर्याप्त संसाधनों के बिना इस विशाल काम का सामना करना मुश्किल होगा।

क्या कश्मीर समस्या 'सुलझ' गई है? एक पूर्ण युद्ध की कगार से वापसी कर, शांति और सुकून की मौजूदा घड़ी बनने तक का यह बदलाव अचानक हुआ। दो परमाणु शक्ति संपन्न ताकतें एक-दूसरे पर बमबारी, ड्रोन हमले, लड़ाकू विमान और नौसेना तैनात करने और सैन्य टुकड़ियों को सक्रिय करते-करते अचानक से युद्धविराम करते हुए, जीत के आपसी दावे तक पहुंच गईं।

जो लोग अंजान हैं, उनके लिए, जैसे पहले स्थिति बनी, फिर पैमाना बढ़ा और फिर अचानक युद्धबंदी हो गई, उन्हें हैरानी हुई होगी- क्या दोनों पक्ष सिर्फ़ नए हथियारों का परीक्षण कर रहे थे ? मगर जानकार के लिए, यह किसी पुराने नाटक का एक अन्य दृश्य है, ऊंचे कोरस गायन सहित। आज़ादी के बाद से, हमने चार युद्ध लड़े हैं व पाक के साथ अनेकानेक झड़पें हुई हैं। विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ, और खूनी संघर्ष एवं घृणा की नींव बना, जिस पर बाद के टकराव आधारित रहे। जम्मू और कश्मीर भारत का एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य है जो कि अब केंद्रशासित प्रदेश है। पाक पूरा कश्मीर पाना चाहता है। यह तथ्य कि पाक के कब्जे वाले कश्मीर सहित, यह इलाका सामरिक रूप से चार मुल्कों (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और भारत) के संगम पर स्थित है, जो इसे और वांछनीय बनाता है।चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई), जिसे नया सिल्क रोड कहा जाता है, उसकी धुरी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, जो कि चीन के शिनजियांग को, पीओके से होकर, ग्वादर से जोड़ता है। यह गलियारा चीनी माल की भूमार्गीय पहुंच मध्य एशियाई देशों से यूरोप तक बनाता है। यह सड़क चीन को बारास्ता ग्वादर तट, आगे समुद्री मार्ग से मध्य पूरबी मुल्कों से भी जोड़ती है। बीआरआई में चीनी अनुबंध और निवेश 124 बिलियन डॉलर का है, जिसमें इस साल की पहली छमाही में 176 से अधिक के अनुबंध हुए हैं। जिससे परियोजना में निवेश 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया। सबसे ज्यादा निवेश अफ़्रीका व मध्य एशिया में हुआ है लिहाजा, कोई आश्चर्य नहीं कि चीन बार-बार पाक सरकार को अपना अगाध समर्थन देता है। हालिया टकराव में भी पाक द्वारा कथित तौर पर चीन निर्मित लड़ाकू विमान, मिसाइलें, संचार, निगरानी उपग्रह और सुरक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया।

मीडिया और बुद्धिजीवियों के उन वर्गों के लिए, जो पाक को एक दिवालिया और आसानी से हराया जाने वाला देश बताते रहते हैं- उनका भू-राजनीति की वास्तविक दुनिया में स्वागत है। पाक उस व्यावसायिक फर्म की तरह है जो कहने को तो अध्याय 11 (दिवालियापन संहिता) में आती हैं, लेकिन अपने देनदारों से तालमेल बिठाते हुए और व्यवस्था से खेल करते हुए, संभावित दाताओं के समक्ष खुद को कैसे पेश करना है, बखूबी जानते हैं।हालिया सैन्य टकराव का पैमाना विस्तारित होकर, लड़ाई के कहीं अधिक जटिल पटल तक फैल गया था।

विकास की आकांक्षाओं के लिए परिवर्तन की बयार

उत्तराखंड पंचायत चुनाव

डा0 जगदीप सिंह

इस बार उत्तराखंड से यह खबर इसलिए खासतौर पर सुर्खियों में है क्योंकि इन चुनावों में सरकारी सेवा से ससम्मान रिटायर होने वाले शिक्षक, प्रधानाचार्य और पुलिस व सेना के ऐसे वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल हैं जिनका अब से पहले राजनीति से कोई लेना-देना नहीं रहा है और जो अपने पैतृक गांव लौटकर ग्राम प्रधान के रूप में उसके विकास का सपना मन में पाले हुए हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड में इस बार माहौल कुछ अलग तरह का नजर आ रहा है। अब जनता लोकतंत्र की इस सबसे छोटी इकाई के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव की उम्मीद पाल रही है और इसमें सामान्य ग्रामीण जन से लेकर बौद्धिक और शिक्षित वर्ग तक की महत्वपूर्ण सहभागिता दिख रही है। गौरतलब है कि इस बार गांवों में बड़ी संख्या में निर्विरोध ग्राम प्रधान चुने गये हैं। यही नहीं, उससे ऊपर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य भी इसमें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 20,820 ग्राम पंचायत सदस्यों समेत कुल 22,429 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गये हैं। इनमें 1361 ग्राम प्रधान, 240 क्षेत्र पंचायत सदस्य और आठ जिला पंचायत सदस्य शामिल हैं।

हालांकि, पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधियों का निर्विरोध चुना जाना कोई नई बात नहीं है लेकिन इस बार उत्तराखंड से यह खबर इसलिए खासतौर पर सुर्खियों में है क्योंकि इन चुनावों में सरकारी सेवा से ससम्मान रिटायर होने वाले शिक्षक, प्रधानाचार्य और पुलिस व सेना के ऐसे वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल हैं जिनका अब से पहले राजनीति से कोई लेना-देना नहीं रहा है और जो अपने पैतृक गांव लौटकर ग्राम प्रधान के रूप में उसके विकास का सपना मन में पाले हुए हैं।

परिवर्तन की यह बयार गढ़वाल क्षेत्र के सुदूर उत्तरकाशी और भिलंगना घाटी से लेकर कुमाऊं के चंपावत और पिथौरागढ़ तक बह रही है। रिवर्स पलायन की इससे बड़ी नजीर भला और क्या हो सकती है! निर्विरोध चुने गये 1361 ग्राम प्रधानों में सबसे ज्यादा खबरों में दो नाम ऐसे हैं जो सेना और पुलिस विभाग में बहुत ही ऊंचे पद से रिटायर होने के बाद अपने सुविधाहीन गांवों में लौट आये हैं जबकि ये भी दिल्ली, देहरादून या किसी सुविधा-संपन्न महानगर में आराम की जिंदगी बसर कर सकते थे। रिवर्स पलायन के विचार को व्यावहारिक धरातल पर उतारते हुए अपने गांव में बसने का निर्णय ले अब ये गांव वालों की आम सहमति से ग्राम प्रधान बन विकास के लिए प्रतिबद्ध दिखते हैं। इनमें पहला नाम है सेना से रिटायर हुए कर्नल यशपाल नेगी का। पौड़ी जिले के बीरोंखाल ब्लाक के वीरगणा गांव के मूल निवासी कर्नल यशपाल नेगी रिटायर होने के बाद अपने गांव लौटने के लिए कृत संकल्प थे। 2020 में जब वह सपत्नीक गांव लौट अपने बंजर पड़े खेतों को आबाद करने की मंशा से खेती-किसानी में जुट गये तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा।आज कर्नल अपने लहलहाते खेतों के साथ जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके इस काम में उनकी पत्नी उनसे भी ज्यादा उत्साहित दिखती हैं। कर्नल यशपाल और उनकी पत्नी निःस्वार्थ भाव से गांव के बच्चों को शिक्षा और स्वरोजगार के प्रति भी प्रेरित कर रहे हैं। यही कारण है कि गांव वालों ने उन्हें एकमत से अपना प्रधान चुन लिया है। गुंजी के ग्रामीणों की इच्छा पर उनके ग्राम प्रधान पद के लिए हामी भरने के बाद सभी दावेदारों ने अपने नाम वापस ले लिए और उन्हें निर्विरोध प्रधान चुन लिया। ऐसे ही टिहरी के अमिल्डा गांव ने अवकाशप्राप्त प्रधानाचार्य दिनेश डंगवाल को निर्विरोध अपना प्रधान चुना है। इनके अलावा भी ऐसे बहुत से शिक्षित और जागरूक ग्रामीण निर्विरोध प्रधान चुने गये हैं जिनका अब से पहले राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है लेकिन अपने गांव के विकास के लिए उनके मन में भरपूर जज्बा है।

पत्रकारिता की आड़ में अपराध

अवनीश गैंग में जुड़े 10 नए नाम

» विकास दुबे के बाद कानपुर का सबसे बड़ा इंटररेंज गैंग

» फोटो जर्नलिस्ट से लेकर टीवी रिपोर्टर तक, मीडिया की आड़ में बन रही थी क्राइम की रणनीति

» 1000 करोड़ की ज़मीन कब्जा साजिश में पहले ही दर्ज हो चुकी है 3200 पन्नों की चार्जशीट

» मीडिया की परछाई में पलता रहा संगठित अपराध

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। पुलिस ने प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित गिरोह पर शिकंजा कसते हुए गैंग के 10 नए सदस्यों के नाम उजागर किए हैं, जिससे कुल सदस्यता अब 26 तक पहुंच गई है। पुलिस ने इसे कानपुर का पहला इंटररेंज गैंग घोषित किया है जो धमकी, वसूली और जमीन कब्जाने जैसे मामलों में लिप्त रहा है। खास बात ये है कि गिरोह के अधिकतर सदस्य मीडिया या पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, जिससे ये लोग आम जनता में अपनी छवि बनाकर आसानी से प्रभाव और पहुंच बना लेते थे।

पुलिस जांच में सामने आए नामों में चकेरी निवासी पत्रकार अमन तिवारी, बिरहाना रोड निवासी फोटो जर्नलिस्ट अभिनव शुक्ला, मोती मोहाल निवासी टीवी पत्रकार रमन गुप्ता, और यशोदा नगर के मोहित बाजपेई समेत अन्य लोग शामिल हैं। हाल ही में राहुल बाजपेई, रमन गुप्ता और जितेंद्र यादव को पुलिस ने सीओडी पुल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

विकास दुबे के बाद दूसरा सबसे बड़ा आपराधिक नेटवर्क

कानपुर के एडिशनल सीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि यह गिरोह एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के बाद सबसे बड़ा संगठित गिरोह है। विकास का गैंग जहां 30 लोगों का था, वहीं अवनीश गैंग अब 26 सदस्यों तक पहुंच चुका है। गैंग में शामिल लोग डकैती, जालसाजी, अवैध कब्जा, गैंगबंदी, और फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए जमीन कब्जाने जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त पाए गए हैं।

28 जुलाई 2024 को 1000 करोड़ रुपये की कीमत वाली मैरी एंड मैरी मेन स्कूल की जमीन कब्जाने की कोशिश में अवनीश दीक्षित और हरेंद्र मसीह समेत 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला कि लेखपाल विपिन कुमार को नजूल अधिकारी बताकर दस्तावेजों की फर्जी कहानी गढ़ी गई थी। मामले में 3200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।

हाई-प्रोफाइल केस, हाई-वोल्टेज कार्रवाई जारी

18 दिसंबर 2024 को कोतवाली थाना प्रभारी संतोष शुक्ला की रिपोर्ट पर दर्ज हुए गैंगस्टर मुकदमे में अवनीश दीक्षित के साथ-साथ हरेंद्र मसीह, राहुल वर्मा, मौरिस, कमला, अभिषेक एरियल समेत कुल 16 लोगों के नाम शामिल थे। बाद में रेल बाजार थाना प्रभारी बहादुर सिंह की जांच में 10 और नाम सामने आए, जिन्हें भी गैंग में शामिल कर लिया गया।

पुलिस का कहना है कि अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। कानपुर पुलिस इस केस को 'जर्नलिज्म-शेल्डेड ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट' के रूप में देख रही है, जो शहर के लिए एक गंभीर सुरक्षा और नैतिक चुनौती बन चुका है।

डीएम ने दिखाई हरी झंडी, खुरपका-मुंहपका से बचाव को विशेष अभियान शुरू

स्वराज इंडिया प्रमुख संवाददाता

कानपुर । जिले में पशुधन को खुरपका-मुंहपका जैसे संक्रामक रोग से बचाने के लिए मंगलवार से विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और अभियान का विधिवत शुभारंभ किया।

यह अभियान भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के अंतर्गत 7 सितम्बर 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य पशुओं को रोगों से सुरक्षित करना और किसानों की आजीविका की रक्षा करना है।अभियान के पहले चरण में जिले के कुल 5,26,370 गोवंश एवं महिषवंशीय पशुओं को नि:शुल्क टीका लगाया जाएगा। इसमें 1,39,400 गोवंश और 3,86,970 महिषवंशीय पशु शामिल हैं। 4 माह से कम आयु के पशुओं, गर्भित मादाओं और छोटे पशुओं को इस चरण में शामिल नहीं किया गया है। टीकाकरण कार्य के लिए 37 टीमें गठित की गई हैं।

प्रत्येक टीम में एक पशु चिकित्सा अधिकारी, एक पशुधन प्रसार अधिकारी तथा सहायक स्टाफ समेत कुल पाँच सदस्य तैनात रहेंगे। टीमें शीत श्रृंखला व्यवस्था के साथ गांव-गांव जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रचार-प्रसार प्रभावी ढंग से किया जाए ताकि कोई भी पशु टीकाकरण से वंचित न रह जाए।

उन्होंने पशुपालकों से अपील की कि वे अपने पशुओं को समय पर उपलब्ध कराएं ताकि इस संक्रामक रोग को जड़ से खत्म किया जा सके।इस अवसर पर कृषि उपनिदेशक डॉ. आर. वर्मा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आई.डी.एन. चतुर्वेदी, डॉ. सुशील कुमार, डॉ. राजेश कुमार, अजय निरंजन व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने किया औचक निरीक्षण

सफाई, अतिक्रमण और विकास कार्यों पर दिए कड़े निर्देश

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने 22 जुलाई को शहर की साफ-सफाई, चल रही परियोजनाओं और अतिक्रमण की स्थिति का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता, जोनल अधिकारी, पर्यावरण अभियंता व स्वच्छता अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने कई जरूरी निर्देश जारी किए और लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई।

नगर आयुक्त ने साफ कहा कि जनता की समस्याओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कार्यों में गति, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

इस निरीक्षण से नगर आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया कि अतिक्रमण, गंदगी और अधूरी परियोजनाओं पर अब ढिलाई नहीं चलेगी। जनता को बेहतर सुविधाएं देने और शहर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में कड़ा रुख अपनाया गया है।

200 मीटर ट्रायल के लिए बनेगी सीएम ग्रिड

किदवई नगर स्थित अलंकार गेस्ट हाउस के पास सीएम ग्रिड रोड परियोजना की समीक्षा की गई। नगर आयुक्त ने सीवर, वॉटर और इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी डक्ट के चल रहे कार्य का जायजा लिया। निर्देश दिया कि तत्काल 200 मीटर का एक आदर्श पैच (Ideal Patch) तैयार किया जाए, ताकि स्थानीय जनता को भविष्य में सड़क के स्वरूप का अंदाजा हो सके।

मिक्की हाउस से सचान गेस्ट तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश

मिक्की हाउस से सचान गेस्ट हाउस तक सड़क के दोनों ओर लगे अस्थाई अतिक्रमण को हटवाने के निर्देश जोनल अधिकारी, जोन-5 को दिए गए। अतिक्रमण के कारण यातायात में बाधा और गंदगी की स्थिति पर अधिकारियों को चेताया गया।

सचान चौराहा से शास्त्री नगर तक सड़क सुधार का आदेश

नगर आयुक्त ने साचन चौराहा से शास्त्री नगर जाने वाली सड़क का निरीक्षण किया।

जल निगम द्वारा खुदी सड़क की दुर्दशा पर नाराजगी जताते हुए तत्काल मरम्मत और समतलीकरण के आदेश दिए, ताकि जनता को आवागमन में परेशानी न हो।

पार्क में अतिक्रमण की जांच के आदेश

वार्ड-51 के एक पार्क में अस्थाई अतिक्रमण की शिकायत पर स्थल निरीक्षण किया गया।नगर आयुक्त ने भू-स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कमला पार्क को 1857 की क्रांति की थीम पर सजाने की योजना तोड़कपुर स्थित कमला पार्क का निरीक्षण किया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि इस पार्क को 1857 की क्रांति की थीम पर विकसित किया जाएगा।इसमें चिल्ड्रन पार्क, बैठने की व्यवस्था, पौधारोपण, स्वास्थ्य अनुकूल हरियाली और लाइटिंग की व्यवस्था होगी।

हत्या का आरोपी जेल से रिहा होते ही बना 'हीरो'

साथियों ने किया भव्य स्वागत, सड़क पर आतिशबाजी और रोड शो

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। नजीराबाद के रंजीतनगर रेलवे लाइन निवासी राहुल राजपूत उर्फ नन्नू की जेल से रिहाई पर आज वीआईपी रोड पर कानून की धज्जियां उड़ती दिखीं। हत्या के प्रयास के गंभीर मामले में आरोपी राहुल को सोमवार को जमानत पर रिहा किया गया। जेल से निकलते ही उसके स्वागत में दो दर्जन से अधिक कारों और करीब 200 बाइकों का काफिला पहुंचा।

साथियों ने जमकर आतिशबाजी की और रोड शो निकाला, जिससे वीआईपी रोड पर भारी जाम लग गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन कहीं नजर नहीं आया, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

चकेरी निवासी रोहित वर्मा पर जानलेवा हमले के मामले में उसकी पत्नी इंद्राणी ने चकेरी थाने में राहुल राजपूत उर्फ नन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी केस में राहुल जेल में बंद था और अब वह जमानत पर बाहर आया है।

प्रशासन मौन, कानून व्यवस्था पर सवाल

शहर में खुलेआम इस तरह का शक्ति प्रदर्शन न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि अपराधियों के बढ़ते हौसले की भी पोल खोलता है।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस प्रकार के जश्न और रोड शो पर तत्काल रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

अरबाज की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा

मोहल्ले के युवकों पर आरोप

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। बाजपेई नगर ऊंचा टीला निवासी 20 वर्षीय अरबाज खान की गला रेतकर की गई हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। हत्या के पीछे मोहल्ले के युवकों से पुरानी रंजिश सामने आई है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

मंगलवार सुबह अरबाज का खून से लथपथ शव उसके घर से करीब 100 मीटर दूर गंगा किनारे मिला। परिजनों ने मोहल्ले में रहने वाले मुस्लिम, उसके भाई अरमान उर्फ कटी, समीर, मुख्तार और शौएब पर हत्या का आरोप लगाते हुए जाजमऊ थाने में तहरीर दी थी।

पुरानी रंजिश में की गई साजिशन हत्या

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि एक सप्ताह पहले से ही साजिश रची गई थी। आरोपियों ने सोमवार रात अरबाज को फोन कर घर से बाहर बुलाया और सुनसान जगह ले जाकर उसकी हत्या कर दी। जांच में सामने आया है कि पूर्व में एक आरोपी को जेल भी भेजा गया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद उसने फिर रंजिश में साथ दिया।मृतक के पिता रियाज, जो टेनरी में काम करते हैं, ने बताया कि सोमवार रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद अरबाज छत पर बैठा था। इसी दौरान उसके मोबाइल पर लगातार कॉल आ रहे थे। रात करीब 12:30 बजे वह कॉल पर बात करते हुए घर से निकला और फिर नहीं लौटा। रातभर परिजन उसे ढूंढते रहे और सुबह उसका शव बरामद हुआ।

डीसीपी गुप्ता ने बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है, बाकी की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर सभी आरोपियों को जेल भेजा जाएगा।

बैंक गई महिला को शातिरों ने बनाया निशाना, खाली हाथ लौटी घर

» सीसीटीवी में कैद हुई दो महिलाओं की करतूत

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। कोतवाली के पास स्थित बैंक ऑफ इंडिया में एक महिला टप्पेबाजों का शिकार बन गई। मंगलवार दोपहर को बैडी अलीपुर निवासी सुनीता ने अपने खाते से बीस हजार रुपए निकालकर पर्स में रखे और पासबुक प्रिंट कराने लगीं। इसी दौरान शातिर महिलाओं ने मौका देखकर उसके पर्स से नकदी उड़ा दी। घटना की भनक तब लगी जब सुनीता ने कुछ देर बाद पर्स देखा, जिसमें रुपए गायब थे। हड़बड़ाकर उन्होंने बैंक स्टाफ को बताया। बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें दो संदिग्ध महिलाएं

उनके बेहद करीब खड़ी दिखीं और चोरी की आशंका उन्हीं पर जताई गई।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। चौकी प्रभारी सचिन सिरोही के अनुसार, फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान की जा रही है, जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा।

दारोगा पर रिश्वत लेकर धमकाने का आरोप, जांच शुरू

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। कस्बा क्षेत्र के बड़ी बाजार निवासी युवक ने पुलिस कस्बा चौकी पर तैनात दारोगा पर रिश्वत मांगने और धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित राजेश कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि पारिवारिक विवाद के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी, जिसकी सूचना आईजीआरएस पोर्टल पर दी गई थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, सोमवार को कस्बा चौकी के एक दरोगा ने उन्हें थाने बुलाया, जहां मौजूद दूसरे दारोगा ने जेल भेजने की धमकी देते हुए 20 हजार रुपये की मांग की। आरोप है कि मौके पर मौजूद राजेश के पिता को जबरन बैठाकर 10 हजार रुपये ले लिए गए और उसके बाद ही छोड़ा गया। दारोगा ने बाकी 10 हजार रुपये जल्द देने की चेतावनी दी। वहीं इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर जांच कराई जा रही है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादक: अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

सड़क पर उड़ती राख ने उड़ाए अफसरों के होश, 42 करोड़ की परियोजना पर सवाल

» नबीपुर-तिलौची फोरलेन में कंक्रीट की जगह बिछाई जा रही थी फैक्ट्री की राख

» स्वराज इंडिया अखबार की रिपोर्ट पर एक्शन में आए PWD के अफसर, जांच के बाद मलबा हटवाया गया

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। योगी सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना के अंतर्गत कानपुर देहात में नबीपुर चौराहे से तिलौची रेलवे स्टेशन तक करीब 3.5 किलोमीटर लंबे फोर लेन मार्ग का निर्माण 42 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा है। यह मार्ग यूपीसीडा की 150 से अधिक औद्योगिक इकाइयों के साथ हजारों ग्रामीणों के लिए कचहरी, अस्पताल और अन्य ज़रूरी सुविधाओं तक पहुंच का मुख्य मार्ग माना जाता है। लेकिन जिस सॉलिड कंक्रीट स्ट्रक्चर की उम्मीद की जा रही थी, उसकी जगह सड़कों पर धूल-धक्कड़ और लापरवाही की परतें चढ़ती दिखीं।

सड़क पर राख डालकर बहाया जा रहा 42 करोड़ का

» नवीपुर-तिलौची फोरलेन सड़क में मिट्टी की जगह उड़ रही फैक्ट्रियों की राख

» मुख्यालय से महज़ 2 किलोमीटर दूर घटिया निर्माण, अफसर बने अनजान

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

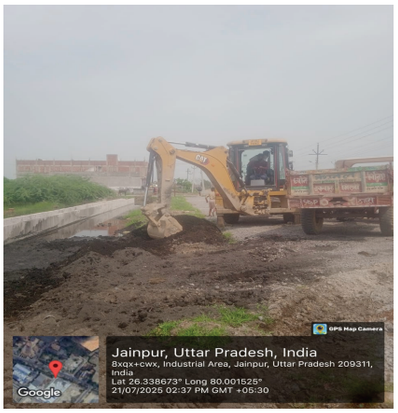

कानपुर देहात। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत कानपुर देहात के नवीपुर चौराहे से तिलौची रेलवे स्टेशन तक 3.5 किलोमीटर लंबे मार्ग का फोरलेन निर्माण 42 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। यह मार्ग केवल यूपीसीडा की ... अधिक ... को ...

स्थानीय लोगों और सूत्रों के मुताबिक, निर्माण में मिट्टी और कंक्रीट की जगह फैक्ट्रियों से निकली राख का इस्तेमाल किया जा ... कई स्थानों पर ... खुले में ... अधिकारियों की ... इस निर्माण की गुणवत्ता पर भारी पड़ रही है। क्षेत्रीय नागरिकों का आरोप है कि अधिकारियों की ... घटिया सामग्री ... किया जा रहा है, नहीं तो माती मुख्यालय और PWD दफ्तर के इतने पास हो रहे निर्माण में यह लापरवाही कैसे अनदेखी रह सकती है?

अफसरों ने माना, जांच के बाद कार्यवाही का भरोसा

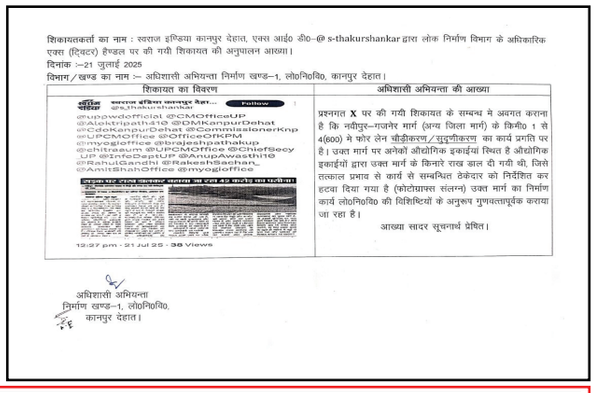

स्थानीय मीडिया द्वारा सवाल उठाए जाने पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने माना कि मिट्टी और कंक्रीट की जगह राख का प्रयोग गलत है और उन्होंने तत्काल जांच की बात कही है। विभाग का दावा है कि दोषी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि जब यह सड़क आम जनता, कारखानों और न्यायिक कामकाज का मुख्य मार्ग है, तो उसकी बुनियाद पर राख क्यों बिछाई जा रही है? क्या जिला प्रशासन और जिम्मेदार विभाग अब भी समय रहते जागेंगे, या फिर सड़क बनने के कुछ ही महीनों में गड्ढों से भरा एक और भ्रष्टाचार की मिसाल बनकर रह जाएगा?

स्थानीय लोगों व सूत्रों के हवाले से सामने आया कि निर्माण कार्य में मिट्टी और कंक्रीट के स्थान पर फैक्ट्रियों से निकलने वाली राख बिछाई जा रही थी। इस गड़बड़ी को लेकर स्वराज इंडिया अखबार ने प्राथमिकता से रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हेमंत कुमार सिंह ने खबर का संज्ञान लिया और तत्काल जांच के निर्देश दिए।जांच में यह स्पष्ट हुआ कि फैक्ट्री संचालकों द्वारा रोड निर्माण स्थल पर राख डाल दी गई थी, जिसे अब हटवा दिया गया है। अधिशासी अभियंता हेमंत कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे की गुणवत्ता जांच जारी रहेगी।

शिकायतकर्ता का नाम : स्वराज इण्डिया कानपुर देहात, एक्स आई0 डी0–@ s-thakurshankar द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैण्डल पर की गयी शिकायत की अनुपालन आख्या।

दिनांक :–21 जुलाई 2025

विभाग / खण्ड का नाम :– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, कानपुर देहात।

शिकायत का विवरण	अधिशासी अभियन्ता की आख्या
स्वराज इंडिया कानपुर देहा... @s_thakurshankar Follow @uppwdofficial @CMOfficeUP @Aloktripath410 @DMKanpurDehat @CdoKanpurDehat @CommissionerKnp @UPCMOffice @OfficeOfKPM @myogioffice @brajeshpathakup @chitraaum @UPCMOffice @ChiefSecy_UP @InfoDeptUP @AnupAwasthi10 @RahulGandhi @RakeshSachan_ @AmitShahOffice @myogioffice सड़क पर राख डालकर बहाया जा रहा 42 करोड़ का पसीना! 12:27 pm · 21 Jul 25 · 38 Views	प्रश्नगत X पर की गयी शिकायत के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि नवीपुर–गजनेर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 1 से 4(600) मे फोर लेन चौड़ीकरण / सुदृणीकरण का कार्य प्रगति पर है। उक्त मार्ग पर अनेकों औद्योगिक इकाईयां स्थित है औद्योगिक इकाईयों द्वारा उक्त मार्ग के किनारे राख डाल दी गयी थी, जिसे तत्काल प्रभाव से कार्य से सम्बन्धित ठेकेदार को निर्देशित कर हटवा दिया गया है (फोटोग्राफ्स संलग्न) उक्त मार्ग का निर्माण कार्य लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक कराया जा रहा है। आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0,
कानपुर देहात।

सभासद ने रोकी विधायक निधि से बन रही सड़क, ग्रामीणों ने किया विरोध

» कमीशन मांगने का ठेकेदार ने लगाया आरोप, मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने जताई नाराजगी

» 25 वर्षों से सड़क का कर रहे थे इंतजार, विरोध में ग्रामीण उतरे सड़कों पर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जनपद के अकबरपुर नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 2 कांशीराम नगर बदलापुर में विधायक निधि से बन रही सड़क को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय सभासद द्वारा निर्माण कार्य रुकवाए जाने से ग्रामीणों में भारी रोष फैल गया।ग्रामीणों ने सभासद पर सड़क निर्माण रोकने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार ने सभासद पर खुले तौर पर कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगाया है।

मामले की सूचना मिलने पर उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला स्वयं मौके पर पहुंचीं और सभासद के रवैए के साथ ही प्रशासनिक उदासीनता पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश देते हुए सड़क निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराया।ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 25 वर्षों से जर्जर मार्ग के कारण आवागमन में परेशानी झेल रहे थे। मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए अपनी विधायक निधि से सड़क निर्माण का कार्य शुरू कराया था, जो तेजी से प्रगति पर था। इस मौके पर बबलू भारती, प्रमोद सिंह केसावत, बउआ पांडेय, महेश तिवारी सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने मंत्री से शिकायत कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

कांवड़ यात्रियों की बस में लगी आग, बड़ा हादसा टला!

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु जब भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हैं, उसी बीच अयोध्या के बैकुंठ धाम से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बुधवार सुबह करीब 6 बजे गोरखपुर के कैंपियरगंज क्षेत्र से आए कांवड़ यात्रियों की बस में आग लग गई। बस (यूपी 58 टी 8058) बालूघाट बांध के पास खड़ी थी। गनीमत रही कि घटना के वक्त बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था।

बस के चालक हरिप्रसाद यादव पुत्र शिवमूरत निवासी रामकोट रेवती, थाना मुंडेरवा, जनपद बस्ती ने बताया कि बस में आग अचानक लग गई। आग लगने की वजह बैटरी में शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। जैसे ही आग लगी, चालक ने तत्परता दिखाते हुए खुद को बस से बाहर निकाला और तत्काल मदद से आग पर काबू पा लिया गया। घटना की सूचना पर कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बस में ग्राम मछलीगांव, थाना कैंपियरगंज, जनपद गोरखपुर से आए कांवड़ यात्री सवार थे, लेकिन सौभाग्यवश घटना के समय सभी यात्री नीचे उतर चुके थे। यदि यह हादसा कुछ मिनट पहले या यात्रियों के बस में रहने के दौरान होता, तो बड़ा नुकसान हो सकता था।

सवाल उठते हैं

–क्या कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा बस ऑपरेटरों के भरोसे छोड़ दी गई है?

–क्या ऐसे धार्मिक आयोजनों में आने वाले वाहनों की जांच नहीं होनी चाहिए?

–नगर प्रशासन और पुलिस ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या योजना बनाई है?

गौरतलब हो कि श्रद्धा का यह पर्व भले ही जल चढ़ाने का है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही इस उत्सव को राख में भी बदल सकती है। अग्निकांड की यह घटना भले ही बिना हताहत के समाप्त हो गई, लेकिन यह एक चेतावनी है अगली बार इतनी किस्मत भी साथ नहीं दे सकती।

निर्माणाधीन सड़क पर हादसा

बड्डूपुर थाना क्षेत्र में पुल निर्माण स्थल बना हादसे का कारण, लखनऊ के युवक को आई गंभीर चोटें

स्वराज इंडिया संवाददाता

निंदूरा,बाराबंकी। विकासखंड निंदूरा के अंतर्गत बड्डूपुर थाना क्षेत्र के ककरहा मजरे कतुरी कला के पास चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य में लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। पुल निर्माण स्थल पर फैली गिट्टी के कारण बाइक सवार युवक अनूप रावत (37) गंभीर रूप से घायल हो गया।

अनूप रावत पुत्र भगौती प्रसाद, निवासी फूलबाग कॉलोनी, थाना गुडंबा, जनपद लखनऊ, अपनी परिचित सवित्री पत्नी सरोज निवासी जहीम नगर, भिठौली, थाना मड़ियांव को उनके ननिहाल महमूदाबाद छोड़ने जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक पुल निर्माण स्थल के पास पहुंची, वहां सड़क पर फैली गिट्टी के कारण उनका नियंत्रण बिगड़ गया और बाइक फिसलकर गिर गई।

गंभीर चोट, अस्पताल में इलाज

हादसे में अनूप रावत को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची बड्डूपुर पुलिस ने तत्काल एंबुलेंस बुलाकर घायल को सीएचसी फतेहपुर भेजा, जहां उनका इलाज जारी है। सवित्री को मामूली चोटें आई हैं।इस मामले पर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही हल्का सिपाही मौके पर पहुंचा और घायल को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। इलाज जारी है, स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।

सवालों के घेरे में निर्माण एजेंसी

स्थानीय लोगों ने निर्माण स्थल पर सुरक्षा के अभाव और सावधानी संकेतों की कमी को हादसे की बड़ी वजह बताया है। पुल निर्माण कार्य के दौरान सड़क पर बिखरी गिट्टी और अव्यवस्थित सामग्री आए दिन राहगीरों के लिए खतरा बनती जा रही है। स्थानीय प्रशासन और निर्माण एजेंसी पर लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं। लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

37 करोड़ का पंप हाउस बना फिर भी डूबा जलवानपुरा

» नगर निगम का दावा भारी, हकीकत शर्मसार!

» जलवानपुरा में अब नाव नहीं, राहत चलेगी-महापौर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी के नाम पर करोड़ों की योजनाएं बनती हैं, ट्रायल और उद्घाटन होते हैं, तामझाम दिखाया जाता है लेकिन जनता का दर्द वैसा का वैसा ही बना रहता है। राम मंदिर से महज एक किलोमीटर दूर स्थित जलवानपुरा मोहल्ला एक बार फिर बरसात में तालाब में तब्दील हो गया, जबकि प्रशासन ने दावा किया था कि अब यहां जलभराव की कोई शिकायत नहीं होगी।

37 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए अत्याधुनिक पंप हाउस की वाहवाही पूरा प्रशासन कर चुका हैं। दावा था कि महज तीन मिनट में 30 हजार लीटर पानी निकाल कर उसे तीन किलोमीटर दूर नाले में भेज दिया जाएगा।

ट्रायल के बाद बारिश हुई तो इस बार की बारिश में फिर वही पुराने दृश्य लौट आए गलियों में पानी, घरों में घुटनों तक जल, और स्थानीय लोग फिर उसी तरह लाचार। लेकिन नगर निगम का कहना है कि एक पम्प ने महज 3 घण्टे में 30 हजार लीटर पानी 3 किमी दूर निकाल दिया।

आश्चर्यजनक यह है कि ट्रायल सफल होने का दावा खुद महापौर और एडीए के अफसरों की मौजूदगी में किया गया था।

मगर हकीकत में जब पानी निकासी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो जनता परेसान रही तो ट्रायल वाला पम्प चला फिर क्या था नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार जो समस्या तीन दिन तक रहती वह तीन घण्टे में खत्म हो गयी। जानकारों का कहना है कि लो लैंड होने के कारण जलवानपुरा में यह समस्या हमेशा रहेगी लेकिन पम्प तो तभी चलेगा जब जलभराव होगा। मतलब की पानी निकलने के लिए जलभराव होना चाहिए।

महापौर गिरीशपति त्रिपाठी और कमिश्नर गौरव दयाल दोनों ने जनता के सामने वादे किए थे कि अब नाव नहीं, राहत चलेगी।

व्यवस्था का असली चेहरा उजागर

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कागजों में चलने वाली योजनाएं और जमीन पर टपकती बूंदों के बीच कितना बड़ा फर्क है। जलवानपुरा का यह जलभराव सिर्फ पानी नहीं है, यह सिस्टम की निकम्मी प्लानिंग और जिम्मेदार अफसरों की असंवेदनशीलता का आईना है। करोड़ों की योजनाएं तब तक बेमतलब हैं जब तक जनता राहत न महसूस करे। अब सवाल यह है जलवानपुरा कब उबरेगा? और क्या वाकई ये पंप सिर्फ ट्रायल के लिए बनाए गए थे?

पम्प का ट्रायल करते महापौर गिरीश पति त्रिपाठी (फाइल फोटो)

प्रशासन एक-दूसरे पर टाल रहा जिमेदारी

एडीए के अधिशासी अभियंता कहते हैं कि अक्टूबर तक प्रोजेक्ट नगर निगम को सौंपा जाएगा, जबकि नगर निगम के अफसर कहते हैं जब तक जिम्मेदारी हमारे पास नहीं आती, हम क्या करें? सवाल ये है कि अगर जनता फिर से डूब रही है, तो उसे इससे क्या फर्क पड़ता है कि जिम्मेदार कौन है?

जनौरा संपर्क मार्ग बना नाला-पाट, नगर निगम के खिलाफ फूटा जनाक्रोश

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। रामराज्य की परिकल्पना करने वाली नगरी में ज़मीनी सच्चाई कुछ और ही कहती है। वजीरगंज के जनौरा लालबाग संपर्क मार्ग पर हर बारिश के बाद नाला नहीं, पूरा रास्ता ही तालाब बन जाता है। नगर निगम के ढुलमुल रवैये और ठेकेदारों की लापरवाही ने इस मार्ग को दलदल में तब्दील कर दिया है।

जिस रास्ते से स्कूली बच्चों को शिक्षा के मंदिर तक पहुंचना चाहिए, वहां उन्हें कीचड़ और बदबूदार पानी में पैर डालकर निकलना पड़ता है। आए दिन गाड़ियां फंसती हैं, राहगीर फिसलते हैं, बच्चे गिरते हैं और नगर निगम आंखें मूंदे बैठा है।स्थानीय निवासी मोहम्मद कादिर की मानें तो शिकायतों का अंबार लग चुका है, पर समाधान अब तक शून्य है। ठेकेदार ने नाला खोद कर छोड़ दिया, और नगर निगम के अफसर समस्या को देखकर भी अंधे बने हुए हैं। गुरुवार को मोहल्ले के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और दर्जनों लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।

बच्चों की सुरक्षा पर संकट-स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे इस रास्ते पर रोज़

अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अभिभावक त्रस्त हैं, पर शासन-प्रशासन को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है। मोहल्ले के लोग स्पष्ट कह रहे हैं – अबकी बार सिर्फ ज्ञापन नहीं, आंदोलन होगा।

जिम्मेदार कौन?- नगर निगम की निष्क्रियता, पार्षदों की चुप्पी और ठेकेदार की गैरजिम्मेदारी ने मिलकर इस मुसीबत को जन्म दिया है। ना नाले की सफाई होती है, ना जलनिकासी की व्यवस्था।

गौर करें प्रशासन-जनौरा मार्ग अब सिर्फ एक सड़क नहीं, जन आक्रोश का रास्ता बन चुका है। स्थानीय लोग शहबाज, सोनू, लकी, बाबू, दुर्गा, दिनेश गुल्लू सिंह, वारिस, आदिल, मोनू, बबलू समेत दर्जनों लोगों ने दो टूक कहा अगर अब भी नहीं जागा नगर निगम, तो अगला कदम आर-पार की लड़ाई होगी।

क्या यह वही अयोध्या है जिसे 'स्मार्ट सिटी' बनने का सपना दिखाया गया था?

नगर निगम जवाब दे नाला सफाई कब होगी? ठेकेदार पर कार्रवाई कब होगी? और बच्चों की जान की कीमत कौन देगा?

अखिलेश यादव ने 'धर्म' को बीजेपी का हथियार बताया

डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बिगड़े बोल, वार-पलटवार का दौर जारी

» रोशन मिश्र, स्वराज इंडिया

लखनऊ। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र की शुरुआत में ही राजनीति में हलचल मचाने वाली खबरें आनी शुरू हो गयी हैं। एक तरफ उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक से अपने पद से इस्तीफा देना चर्चा का विषय बना हुआ है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी एक सांसद, कैबिनेट मंत्री और आये दिन अपने वक्तव्य को लेकर विपक्षी पार्टियों के निशाने पर रहने वाले गिरिराज सिंह का मीडिया वार्ता के दौरान यूपी के पूर्व मुख्यमन्त्री अखिलेश यादव से गले मिलना सुर्खियां बटोर रहा है।

विपक्षी दलों के कुछ समर्थक उन्हें बीजेपी की बी-टीम होने का तमगा दे रहे हैं। लोग इस दृश्य को लेकर तरह-तरह की चचाएं कर रहे हैं। इसकी कुछ झलकियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी और पढ़ी जा सकती है। इस दौरान आज जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से अगले उप-राष्ट्रपति पद के लिये बीजेपी के लोगों की तरफ से बिहार के सीएम नितीश कुमार के नाम को लेकर सवाल पूछा तो सपा अध्यक्ष ने बड़े ही सफाई से यह कह कर किनारा कर लिया, "मुझे नहीं पता कि अगला उप-राष्ट्रपति कौन बन रहा है लेकिन बीजेपी के लोगों को मांग करनी चाहिये कि कम से कम उप-राष्ट्रपति जी के लिये फेयरवेल पार्टी तो हो।"

बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग को लेकर सपा अध्यक्ष के तीखे बोल जारी हैं

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बीजेपी सरकार के साथ-साथ चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब देते हुये कहा, "आप सभी पत्रकार बंधु समझदार हैं इसलिये आप लोगों को कहीं और न देखकर सीधे सोशल मीडिया और गूगल पर जाकर केवल उत्तर प्रदेश बाइ-इलेक्शन टाइप कर देना है क्योंकि जिस समय आप लोग उत्तर प्रदेश बाइ-इलेक्शन की जानकारी हासिल करेंगे, उसी समय आपको पूरे इलेक्शन कमीशन की पोल खुलती नज़र आयेगी।"

बीजेपी सरकार पर प्रहार करते हुये श्री यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि आपको वोट डालने नहीं दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकार हर मौके पर अन्याय करती है और कोई भी मौका अन्याय करने का छोड़ती नहीं है।

सपा अध्यक्ष ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुये बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुये कहा कि आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफहै कि कोई जुड़े नहीं दूरियां बनी रहे क्योंकि बीजेपी का हथियार ही धर्म है। यह बात आप सभी लोग जानते हैं। अखिलेश यादव ने पसमांदा मुस्लिम समाज के मुद्दे पर कहा कि समाजवादी पार्टी और नेताजी के साथ पिछली सरकारों में जो भी काम हुये थे, खासकर पसमांदा और बुनकर समाज के लिये, उन सभी कामों को रोक दिया गया। सपा अध्यक्ष ने कहा, यदि बीजेपी को पसमांदा समाज की इतनी ही फिक्र है तब वे एक काम कर दें कि जो काम समाजवादी पार्टी और नेताजी ने मुफ्त बिजली देकर किया था, ये लोग भी बिजली को मुफ्त कर दें। इसके साथ ही उन्होंने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा पर चुटकी लेते हुये कहा कि आप लोग यूपी के बिजली मंत्री का हाल देख सकते हैं। वे जहां भी जाते हैं, वहां बिजली ही चली जाती है।

बिहार में चल रहे "सर"- स्पेशल इंटेंसिव रिविजन अभियान को लेकर जब पत्रकार ने अखिलेश यादव ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, "स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (सर) के सवाल पर हम विपक्ष के सभी लोग एक साथ ही हैं क्योंकि चुनाव आयोग पर समय-समय पर उंगली उठी है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि लोग अधिक से अधिक मतों का प्रयोग कर सकें।"

यूपी के उप मुख्यमन्त्री केशव प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल

पूर्व सीएम अखिलेश यादव की कल एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें वे कुछ मुस्लिम समाज के लोगों के साथ औपचारिक मुलाकात करते हुये नजर आ रहे थे। हालांकि, हम इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करते। इसके बाद बुधवार को उप मुख्यमन्त्री केशव प्रसाद मौर्य के 'एक्स' हैंडल से एक पोस्ट की जाती है। इस पोस्ट पर उन्होंने लिखा है, "मस्जिद गए लेकिन सफेद 'जालीदार टोपी' ले जाना भूल गए सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव। जब ख्याल ही रखना था तो कब्जा करने वाली जमात का पूरा ख्याल रखना चाहिये था।" इसके अलावा उप मुख्यमन्त्री ने एक और पोस्ट ट्वीट किया था। उनके एक्स हैंडल पर सपा अध्यक्ष के लिये लिखा गया, "कब्जाधारी सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव के अपने शासन में अवैध कब्जा वाले कृत्य पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। दरअसल, 'लठैतवाद' के सिद्धांत में भरोसा करने वाले सपाई जिस जमात का साथ पसंद करते हैं, उनका 'पहला उसूल' ही कब्जा करना होता है।"

लिया जायजा | **जाना गांव स्थित कान्हा गौशाला के 5346 गोवंशों की व्यवस्था पर संतोष जताया**

कान्हा गौशाला पहुंचे नगर आयुक्त, देखे इंतजाम

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर आयुक्त सुधीर कुमार द्वारा बुधवार को जाना गांव स्थित कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. निरंजन, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिल्पा सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में गौशाला में कुल 5346 गोवंश मौजूद हैं। इनके लिए 10838 कुंतल भूसा का भंडारण किया गया है, प्रतिदिन 430 कुंतल हरा चारा और

40 कुंतल चुनी/चोकर की व्यवस्था की जा रही है। गौशाला में स्वच्छ पेयजल और सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था भी सुचारु रूप से संचालित हो रही है।

बरसात से बचाव और स्वास्थ्य सुरक्षा : वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए 9 बड़े शेड बनाए गए हैं, ताकि बरसात के दौरान गोवंशों को सुरक्षित आश्रय मिल सके। अब तक 5220 गोवंशों की टैगिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है और एचएस टीकाकरण का कार्य आगामी सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। गौशाला में 45 कर्मचारी एवं 9 सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। परिसर में सक्रिय सीसीटीवी कैमरे, संतोषजनक सफाई व्यवस्था और गोबर प्रबंधन की भी समीक्षा की गई। साथ ही 8 स्थानों पर ग्रीन बेल्ट विकास कार्य भी प्रगति पर है।

मॉडल एबीसी सेंटर की प्रशंसा : निरीक्षण में यह भी पाया गया कि गौशाला परिसर में मॉडल एबीसी (एनीमल बर्थ कंट्रोल) सेंटर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। यह सेंटर कुशलता से संचालित हो रहा है, जहां रोजाना लगभग 30 कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। सेंटर में 2 वेटनरी सर्जन सहित संपूर्ण एबीसी टीम सक्रिय है। निरीक्षण के अंत में नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि "गौशाला में जो भी कार्य शेष हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए और इसे एक आधुनिक मॉडल गौशाला के रूप में संरक्षित रखा जाए।"